

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 05, सोमवार, शाके 1946 - फरवरी 24, 2025 Phalguna 05, Monday, Saka 1946- February 24, 2025	

भाग-1(ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
उर्जा विभाग
प्ररूप-7
(देखिए नियम 16 का उप-नियम(1))
प्रारंभिक अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 28, 2025

संख्या प0 16(13)उर्जा/2024/03307 :-भूमि अवाप्ति अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन (132 के.वी.जी.एस.एस. आर.वी.पी.एन.) के लिए बीनासर ग्राम जिले के कुल 3.0604 हैक्टर भूमि अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त परियोजना के लिए जिला-चुरू, के ग्राम-बीनासर में 3.0604 हैक्टर भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	संपूर्ण क्षेत्रफल (है.)	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	शीर्ष का प्रकार	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	
1.	बीनासर	3.0604	965/403	बारानी	निजी	प्रेमादेवी पत्नी श्री रूकमा नन्द निवासी छाजूसर तहसील चुरू	रास्ता	639/403, 403	रास्ता	964/403	खेजड़ी	25	शून्य

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चुरू, जिला चुरू के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षित किया जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारी वर्ग को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, भूमि का स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

या अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

चूँकि धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजनाओं के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प0 16(13)उर्जा/2024/03307 जयपुर, दिनांक:- 24.12.2024 के द्वारा सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन ना करने का विनिश्चय किया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

गिरधर,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।